अटल भूजल योजना-भूजल के लिए योजना की आवश्यकता क्यों

लेखक - हरिकिशन शर्मा (संपादक)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-I (भूगोल) एवं III (पर्यावरण) से संबंधित है।

इंडियन एक्सप्रेस

27 दिसम्बर, 2019

"देश के भूजल संसाधनों पर बढ़ती चिंताओं के बीच अटल भूजल योजना की शुरुआत की गई है। इस आलेख में हम इन संसाधनों की कमी और इस तरह के मुद्दों को दूर करने के लिए इस योजना की प्रासंगिकता पर एक नजर डालेंगे।"

बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के एक दिन बाद अटल भुजल योजना या अटल जल का शुभारंभ किया। अटल जल विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित केंद्रीय योजना है जिसका उद्देश्य भूजल प्रबंधन में सुधार करना है। इसे विश्व बैंक बोर्ड ने जून 2018 में मंजूरी दी थी।

भूजल संसाधनों की कमी को देखते हुए इसका विचार पहली बार 2015 में सामने आया था। सरकार ने 2016-17 के बजट में भूजल संसाधनों के प्रबंधन के लिए एक कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की थी, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 6,000 करोड़ रुपये है।

अटल भूजल योजना

चर्चा में क्यों?

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर 2019 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 95वीं जयंती के अवसर पर 'अटल भूजल योजना' की शुरुआत की।
- इस योजना के जरिए भूजल का प्रबंधन किया जाएगा तथा प्रत्येक घर तक पीने के स्वच्छ पानी को पहुँचाने की योजना पर काम होगा।
- केंद्र सरकार ने इस योजना हेतु 6000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इसमें से 3000 करोड़ रुपये विश्व बैंक और 3000 करोड़ रुपये केंद्र सरकार देगी। इस योजना पर पाँच साल में 6000 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
- सरकार ने इन क्षेत्रों में भूजल दोहन के स्तर के अनुसार इस योजना के लिए सात राज्यों का चयन किया है।
- सरकार ने इन क्षेत्रों को उनकी संस्थागत तत्परता, गिरावट, स्थापित कानूनी और विनियामक साधनों, और भूजल प्रबंधन से संबंधित पहलों को लागू करने में अनुभव के कारण भी चुना है।

भारत में पानी कितना दुर्लभ है?

भारत दुनिया की आबादी के 16 प्रतिशत हिस्से का भागीदार है, जिसका निवास क्षेत्र वैश्विक क्षेत्र के 2.5 प्रतिशत से भी कम है और वैश्विक जल संसाधनों के मामले में इसकी भागीदारी सिर्फ 4 प्रतिशत है। केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) के अनुसार, देश की अनुमानित जल संसाधन क्षमता, जो नदियों में प्राकृतिक अपवाह के रूप में होती है, 1,999 बिलियन क्यूबिक मीटर है। इसमें से अनुमानित उपयोग योग्य संसाधन प्रति वर्ष 1,122 बिलियन क्यूबिक मीटर है जिसमें 690 बीसीएम प्रति वर्ष सतही जल और 432 बीसीएम प्रतिवर्ष पुनर्भरणीय भूजल है।

आबादी बढ़ने के साथ-साथ आने वाले वर्षों में पानी की माँग कई गुना बढ़ जाएगी। सीडब्ल्यूसी के अनुसार, देश में प्रति व्यक्ति उपलब्धता 2025 में 1,434 क्यूबिक मीटर से घटकर 2050 में 1,219 क्यूबिक मीटर हो जाएगी।

सीडब्ल्यूसी के बेंचमार्क के अनुसार, पानी पर जोर देने की स्थिति तब होती है जब प्रति व्यक्ति उपलब्धता 1,700 क्यूबिक मीटर से कम होती है और पानी की कमी की स्थिति तब होती है जब प्रति व्यक्ति उपलब्धता 1,000 क्यूबिक मीटर से कम हो जाती है। कुछ नदी बेसिन को पानी की कमी की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। इनमें सिंधु (सीमा तक), कृष्णा, कावेरी,

सुवर्णरेखा, पेन्नार, माही, साबरमती और पूर्व में बहने वाली नदियों सहित लूनी, कच्छ और सौराष्ट्र की पश्चिम में बहने वाली नदियाँ हैं। कावेरी, पेन्नार, साबरमती और पूर्व में बहने वाली नदियों और लूनी सहित कच्छ और सौराष्ट्र की पश्चिम में बहने वाली नदियों में पानी की कमी सबसे तीव्र है।

भूजल की स्थिति क्या है?

सीडब्ल्यूसी द्वारा प्रकाशित 'वाटर एंड रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स, 2019' रिपोर्ट के अनुसार, भारत (2017) में वार्षिक पुन:पूर्ति योग्य भूजल संसाधन 432 बीसीएम है, जिसमें से वार्षिक निकालने योग्य भूजल उपलब्धता 393 बीसीएम है। देश में भूजल क्षमता का लगभग 90 प्रतिशत हिस्से का भार पंद्रह राज्यों पर है। जिसमें से उत्तर प्रदेश की हिस्सेदरी 16.2 प्रतिशत, मध्य प्रदेश (8.4%), महाराष्ट्र (7.3%), बिहार (7.3%), पश्चिम बंगाल (6.8%), असम (6.6%), पंजाब (5.5%) और गुजरात (5.2%) है।

वर्तमान वार्षिक भूजल निष्कासन 249 बीसीएम है, जिसमें सिंचाई क्षेत्र की भागीदारी सबसे अधिक है। यही कारण है कि सरकार ने धान और गन्ने जैसी जल-सघन फसलों के विकल्पों का आह्वान किया है।

हाल ही में संसद में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा दिए गए एक उत्तर के अनुसार, 2009-18 के लिए एक दशकीय औसत की तुलना में, केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB) द्वारा निगरानी किए गए कुओं के भूजल स्तर में 61% की गिरावट आई है। जिन राज्यों में कम से कम 100 कुओं की निगरानी की गई, उनमें सबसे अधिक कमी कर्नाटक (80%), महाराष्ट्र (75%), उत्तर प्रदेश (73%), आंध्र प्रदेश (73%), पंजाब (69%) में हुई है।

केंद्रीय भूजल बोर्ड की भूमिका क्या है?

बोर्ड हर साल जनवरी, मार्च-मई, अगस्त और नवंबर में 23,196 'नेशनल हाइड्रोग्राफ मॉनिटर स्टेशनों' (6,503 खोदे गए कुएं और 16,693 पाईजोमीटर) के नेटवर्क के माध्यम से जल स्तर और गुणवत्ता की निगरानी करता है। पाईजोमीटर एक उपकरण है जो बोरहोल में भूजल के दबाव या गहराई की निगरानी के लिए रखा जाता है।

भूजल संसाधनों के संदर्भ में केंद्रीय भूजल बोर्ड ने देश की मूल्यांकन इकाइयों (ब्लॉक, तालुका, मंडल आदि) को सुरक्षित, अर्ध-महत्त्वपूर्ण और अति-शोषित में वर्गीकृत किया है। अति-शोषित इकाइयों की संख्या 2017 में 839 से बढ़कर 2017 में 1,186 हो गई है। उत्तर में, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में 60% से अधिक मूल्यांकन इकाइयाँ अति-शोषित हैं। संसद के मानसून सत्र

अटल भूजल योजना क्या है?

- यह योजना उन क्षेत्रों में भूजल स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई है जहां यह काफी नीचे चला गया है। योजना का मुख्य उद्देश्य भूजल का स्तर बढ़ाना है। साथ ही, यह योजना केंद्र सरकार द्वारा किसानों को लाभ प्रदान करने के लिए लाई गई है।
- केंद्र सरकार इस योजना के तहत् किसानों के लिए पर्याप्त जल भंडारण सुनिश्चित करना चाहती है। इस योजना के तहत् सात राज्यों के 8350 गांव लाभान्वित होंगे। भूजल के संरक्षण हेतु शैक्षणिक और संवाद कार्यक्रमों को संचालित किया जायेगा।
- इस योजना से महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात इन सात राज्यों के भूजल का लाभ उठाने में बहुत सहायता मिलेगी। इन सात राज्यों के 78 जिलों में 8,350 ग्राम पंचायतों में भूजल की स्थिति बहुत ही चिंताजनक है।
- इस योजना में आम लोगों को भी शामिल किया जाएगा। जल सुरक्षा के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर काम किया जाएगा।
- इस योजना के तहत् राज्यों में स्थायी भूजल प्रबंधन के लिए संस्थागत प्रबंधनों को मजबूत बनाया जाएगा। अटल भूजल योजना के तहत् साल 2024 तक हर घर में पीने का पानी पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है।

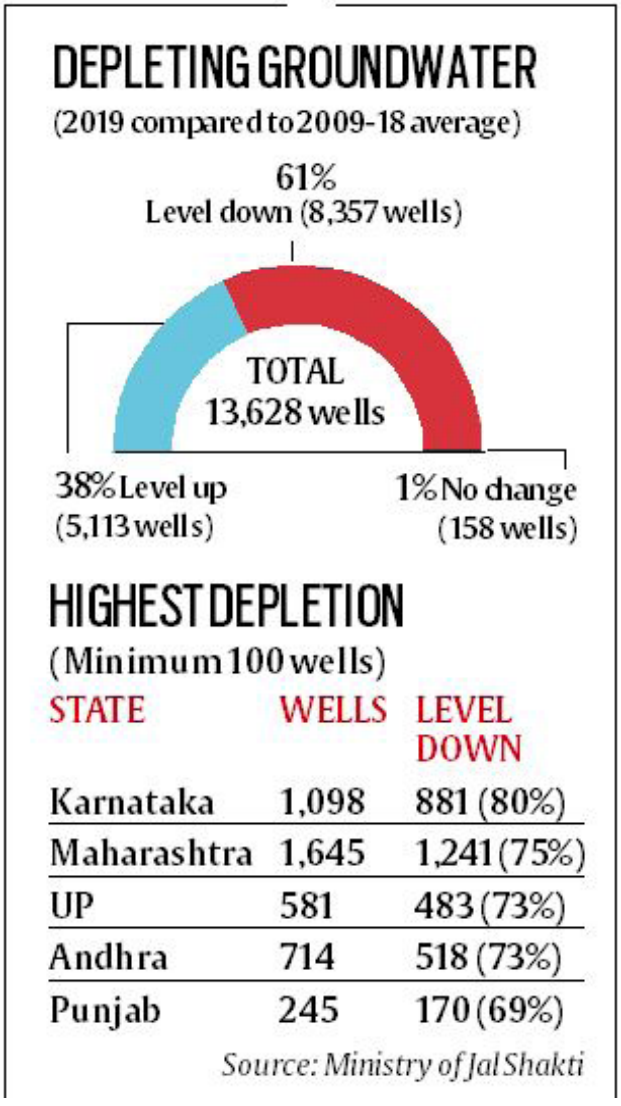

के दौरान, जल शक्ति मंत्रालय ने कहा था कि देश की 14% आकलन इकाइयाँ अर्ध-संकटपूर्ण स्थिति में हैं, 5% संकटपूर्ण हैं और 17% 2017 तक अति-शोषित हैं।

योजना द्वारा इसमें से कितने को संबोधित किया जाएगा?

अब, अटल भूजल योजना को सात राज्यों - गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और यूपी में 2020-21 से 2024-25 तक पाँच वर्षों में लागू किया जाएगा। उम्मीद है कि इससे 78 जिलों की लगभग 8,350 ग्राम पंचायतों को फायदा होगा। जल शक्ति मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, यदि यह योजना जल-दबाव वाले क्षेत्रों में अपने उद्देश्यों को पूरा करती है, तो इसे देश के अन्य भागों में विस्तारित किया जाएगा।

अटल भूजल योजना क्यों?

- प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 'अटल भूजल योजना' में एक प्रावधान किया गया है, जिसमें बेहतर प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायतों को अधिक आवंटन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले 70 वर्षों में, 18 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से केवल 3 करोड़ के पास पाइप जलापूर्ति की सुविधा पहुँच पाई है।
- अब सरकार ने पाइपों के जरिए अगले 5 वर्षों में 15 करोड़ घरों में पीने के स्वच्छ पानी की सुविधा पहुँचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

पृष्ठभूमि

- मोदी सरकार ने मार्च 2018 में 'अटल भूजल योजना' का प्रस्ताव रखा था।
- इस योजना को विश्व बैंक की सहायता से 2018-19 से 2022-23 की पांच वर्ष की अवधि में कार्यान्वित किया जाना है।
- इस योजना का लक्ष्य भूजल का गंभीर संकट झेल रहे सात राज्यों में सबकी भागीदारी से भूजल का उचित और टिकाऊ प्रबंधन करना है।

इन उद्देश्यों को कैसे पूरा किया जाएगा?

भूजल स्तर में गिरावट के साथ-साथ पानी की खपत को रोकने पर ध्यान दिया जाएगा। यह योजना संस्थागत ढाँचे को मजबूत करने और स्थायी भूजल संसाधन प्रबंधन के लिए सामुदायिक स्तर पर व्यवहारिक बदलाव लाने की कोशिश करेगी। यह समुदाय के नेतृत्व वाली जल सुरक्षा योजनाओं की परिकल्पना करता है।

हमारे पास 2013 से देश के भूजल संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए एक भूजल प्रबंधन और विनियमन योजना है। यह नई योजना एक अद्यतन और संशोधित संस्करण है। अवधारणाओं को जल उपयोगकर्ता संघों और जल बजट के रूप में पेश किया जाएगा। बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों और पंचायतों को अधिक धनराशि मिलेगी।

इसके लिए वित्त कहाँ से आएगा?

6,000 करोड़ रुपये में से 3,000 करोड़ रुपये का योगदान विश्व बैंक द्वारा ऋण के रूप में किया जाएगा जबकि अन्य आधा केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय सहायता के रूप में प्रदान किया जाएगा। यह सभी राज्यों को विश्व बैंक घटक और केंद्रीय सहायता अनुदान के रूप में दिया जाएगा।

GS World Committed To Excellence

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. अटल भूजल योजना के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

   1. अटल भूजल विश्व बैंक एवं केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है।
   2. इस योजना हेतु कुल 6500 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
   3. यह योजना भूजल स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई है।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

   (a) केवल 1 (b) 1 और 3

   (c) केवल 2 (d) 1, 2 और 3

Expected Questions (Prelims Exams)

1. **Consider the following statements in the context the Atal Bhujal Yojana.**

   1. Atal Bhujal Yojana is a scheme sponsored by World Bank and Central Government
   2. A total of 6500 crores Rs. has been allocated for this scheme.
   3. This scheme has been launched with the objective of increasing the ground water level.

   Which of the above statements is/are correct?

   (a) Only 1 (b) 1 and 3

   (c) Only 2 (d) 1, 2 and 3

नोट : 26 दिसम्बर को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1 (b) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न: 'भारत में भौम जल के गिरते स्तर तथा सार्वभौमिक पेय जल की अनुपलब्धता की समस्या के समाधान हेतु अटल भूजल योजना एक बेहतर कदम सिद्ध हो सकती है।' इस कथन का विश्लेषण कीजिए।

(250 शब्द)

Atal Bhujal Yojana can prove to be a better step to solve the problem of receding ground water level and non-availability of universal drinking water in India. Analyze this statement.

(250 words)

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।